खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) मध्य प्रदेश में चूना-पत्थर, डोलोमाइट, मैंग्नीज तथा बाक्साइट भंडारों वाले बहुत बड़े भू-क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विदोहन के लिए आरक्षित किया गया है ।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 35 गांवों, छिन्दवाड़ा जिले में 3 गांवों सतना जिले में 182 गांवों तथा बिलासपुर जिले में 67 गांवों में चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंग्नीज वाले क्षेत्रों का आरक्षण समाप्त करने की सहमति दे दी है ।

अनुसूची-1 से खनिजों का निकाला जाना

1719. **श्री कैलाश नारायण सारंग** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय खनिज नीति के अंतर्गत आने वाले खनिजों के अतिरिक्त अन्य खनिजों को अनुसूची-1 से निकालने का विचार रखती है ;

(ख) चूना-पत्थर, डोलोमाइट, बाक्साइट, जैसे खनिजों को, जो कि बहुतायत में पाये जाते हैं, अनुसूची-1 में रखने का क्या प्रयोजन है ;

(ग) क्या इन खनिजों के खनन के लिए रियायतें प्रदान करने से पहले केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेना जरूरी है और

(घ) क्या सरकार इन खनिजों के पट्टे पर खनन के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने की शर्त को हटाने पर विचार करेगी ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची में दर्ज खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे मंजूर करने के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति लेनी होती है । इससे पूरे देश में महत्वपूर्ण खनिजों का योजनाबद्ध और क्रमबद्ध विदोहन सुनिश्चित होता है । इस अनुसूची से कुछ खनिजों को हटाने के प्रश्न पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है ।

हिमाचल प्रदेश में खानों और खनिजों का सर्वेक्षण

1720. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के किन-किन स्थानों पर किन-किन तारीखों को किन-किन खनिजों की खानों का सर्वेक्षण कार्य किया गया था और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ख) हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की गड्सा घाटी में नरौल नामक स्थान पर तांबे की खान से संबंधित सर्वेक्षण कार्य कब से चल रहा है ;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस पर कितनी राशि खर्च किये जाने का अनुमान है ; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हिमाचल प्रदेश में किए गए सर्वेक्षण के फलस्वरूप, 1989-90 में कुल्लू जिले में गरशा घाटी में तांबा; 1990-91 में सिरमौर जिले में अनियार अम्बोता में सीसा व जस्ता; 1990 में कुल्लू जिले में उचिच में चांदी और सीसे के भंडार; 1959-60 में बारासीगड़ी जिला लाहौल-स्पीति में एन्टीमनी अयस्क भंडार ; 1988-91 में किन्नौर जिले में पुरबानी क्षेत्र में टिन-टंगस्टन; 1985-86 में बिलासपुर और उना जिलों के घुमारविन क्षेत्र में स्वर्ण का पता लगाया गया है ।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 1965-87 में किए गए पहले के सर्वेक्षण से, सिरमौर, शिमला, बिलासपुर, कांगड़ा जिलों में 956.35 मि० टन चूना-पत्थर (सभी

ग्रेड); किन्नौर जिले में 1.25 मिलियन टन जिप्सम; मण्डी जिले में 7.5 मिलियन टन रॉक-साल्ट तथा कांगड़ा और चम्बा जिलों में 22.2 मि० टन रूफिंग स्लेट के भंडारों की पुष्टि की गई है ।

(ख) तांबे के लिए सर्वेक्षण और गवेषण का काम भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 1988–89 में आरम्भ किया गया था । नरशा, पार्वती घाटी, कुल्लु जिले में अभी भी चल रहा है ।

(ग) 1991-92 के दौरान इस क्षेत्र में सर्वेक्षण पर 248,288 रु० खर्च किए गए । चालू वित्त वर्ष 1992–93 के दौरान लगभग 9,25,000 रु० खर्च किये जाने की संभावना है ।

(घ) प्रारम्भिक गवेषण रिपोर्ट से नरशा घाटी में 200 मी० लम्बे क्षेत्र में 0.86 से 1.95 मी० की चौड़ाई पर 0.17% से 2.44% तांबा खनिज का पता चला है । यहां आगे कार्य चल रहा है और इसके 1994 तक पूरा होने की संभावना है ।

Mineral Deposits in Arunachal Pradesh

1721. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that large deposits of coal, iron, limestone, mica and uranium have been descovered in Arunachal Pradesh;

(b) if so, the grade of the deposits and its estimated quantity; and

(c) by when Governemnt propose to undertake mining of those mineral deposits?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) to (c) Deposits of coal and limestone have been discovered in Arunachal Pradesh Geological Survey of India has estimated the recoverable reserves of coal as on 1-1-90 to be of the order of 31 million tonnes, 11 million tonnes and 48 million tonnes in proved, probable and possible categories respectively. The recoverable reserves of limestone as on 1-1-85 were reported to be 108 million tonnes in possible category.

Mining of these deposits can be taken up only after grades of these minerals have been determined and the size of their reserves firmed up on the basis of detailed prospecting of the area. As per provisions of the Mines and Minerals (Regulation & Development) Act, 1957, the State Government can take up such detailed prospecting on its own or issue licences for this purpose.

New Mineral Development Policy

1722. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether Government are formulting a New Mineral Development Policy for the 8th Five Year Plan;

(b) if so, what are the details there-of;

(c) the present status of the proposal and areas identified for private participation investment; and

(d) the redeeming features of the new Policy?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) to (d) The National Mineral Policy announced in 1990 will hold good, by and large, for the 8th Five Year Plan. It is, however, being reviewed especially in regard to (a) the need for reservation of the exploitation of certain mineral resources for the public sector; (b) the extent of foreign participation permissible in the mineral sector.